

भारत सरकार  
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1317  
11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

प्राकृतिक मोती उत्पादन

+1317. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में प्राकृतिक मोतियों की भारी मांग के चलते प्राकृतिक मोती का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार के पास राज्यों द्वारा वार्षिक प्राकृतिक मोती उत्पादन के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा प्राकृतिक मोतियों के बाजार और प्रमाणन को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री  
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से प्राकृतिक मोती की खेती (नैचुरल पर्ल फारमिंग) को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। मत्स्यपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलों में शामिल हैं (i) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 461.00 लाख रुपए की कुल लागत से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत अनुमोदित 2307 बाइवाल्व कल्चिवेशन इकाइयां (मसल्स, क्लैम्स, मोती आदि) (ii) मत्स्यपालन विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर प्राकृतिक मोती की खेती और इसके आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मोती किसानों को सहायता (iii) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत पर्ल क्लस्टर सहित मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रसारित की गई। (iv) झारखंड सरकार के सहयोग से हजारीबाग, झारखंड में प्रथम पर्ल क्लस्टर उत्पादन विकास और प्रसंस्करण की अधिसूचना और (v) समुद्री मोती सीप की प्राकृतिक आबादी को बढ़ाने के लिए, आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) ने तमिलनाडु तट के तूतीकोरिन क्षेत्र में 1.65 करोड़ हैचरी उत्पादित सीड रैंच किए है।

(ख) और (ग): गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, केरल, राजस्थान, झारखंड, गोवा और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में मोती पर्ल कल्चर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार प्राकृतिक मोती उत्पादन के आंकड़े सूचित नहीं किए गए है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने बताया है कि झारखंड के हजारीबाग जिले में 1.02 लाख मोती उत्पादित हुए हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने प्राकृतिक मोतियों की मारकेट लिंकेज को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकें की हैं।

\*\*\*\*\*